

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तैयार कर रहा योजना, जून में फैसले की संभावना

यूपीआई से खरीदारी पर छूट की तैयारी

विशेष

■ **धीरेद्री कुमार**

नई दिल्ली। जल्द ही यूपीआई कोड स्कैन करके खरीदारी करना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से सस्ता हो सकता है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूपीआई से होने वाली खरीदारी पर ग्राहकों को छूट मिलेगी। प्रस्तावित योजना यूपीआई के फायदों को ग्राहकों तक पहुंचाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए है।

इस मामले से जुड़े तीन उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय जल्द ही उद्योग के हितधारकों के साथ इस संबंध में बैठक करेगा। वर्तमान में जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड स्वाइप से भुगतान करता है तो दुकानदार को 2-3% की फीस देनी पड़ती है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट (एमडीआर) कहा जाता है। यह फीस बैंक और बीजा या मास्टरकार्ड जैसी पेमेंट गेटवे कंपनियों को जाती है। ज्यादातर दुकानदार यह

सैंसेक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट

मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 271 अंक और टूट गया।

मूडीज रेटिंग्स के अमेरिका की साख घटायें जाने के बीच कमजोर रुख के साथ आईटी और बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया।

निवेशकों ने आईटी, पूंजीगत सामान और तेल एवं गैस शेयरों में मुनाफावसूली की।

चोकसी को 2.1 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। सेबी ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लि. के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा है।

नियामक ने 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति के साथ बैंक खाते भी कुर्क करने की चेतावनी दी है। जनवरी 2022 में लगा जुर्माना न देने पर नोटिस भेजा गया है।

तीन कंपनियों की बकाया माफी याचिका खारिज की

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाया माफ करने की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महांदेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है। पीठ ने वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं जो हमारे सामने आई हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती। हम इसे खारिज करेंगे। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की मदद करने की सरकार की इच्छा के रास्ते में आने से इनकार किया। रोहतगी ने सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में जुलाई तक स्थगन की मांग की। जब अदालत ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह इस बात की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या अदालत को पेशान किए बिना कुछ समाधान खोजा जा सकता है।

सोना और चांदी में उछाल दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की माफिक 580 रुपये बढ़कर 97,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी 500 रुपये बढ़कर 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल 4.5 प्रतिशत के करीब पहुंच रहा है, हालांकि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग को 'एएए' से घटाकर एए1 कर दिया है।

सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश 23 प्रतिशत उछला

नई दिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड परिसंपत्तियों का आकार वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 65.74 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उद्योग निकाय एम्फ्री ने सोमवार को यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2023-24 में म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन-अधीन परिसंपत्तियां 53.40 लाख करोड़ रुपये थीं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ्री) की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, आलोच्य वित्त वर्ष में इक्विटी एवं ऋण बाजारों में तेजी के बीच मजबूत शुद्ध प्रवाह और निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि से होने वाले लाभ के कारण एयूएम का आकार बढ़ा है। उद्योग निकाय ने एयूएम में वृद्धि का श्रेय वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 8.15 लाख करोड़ रुपये तक के शुद्ध प्रवाह को भी दिया है। परिसंपत्ति आधार में जब उछाल निवेशकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों की बढ़ती संख्या में भी परिलक्षित हुआ। पोर्टफोलियो की संख्या 23.45 करोड़ के सर्वाकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई और निवेशक आधार भी लगभग 5.67 करोड़ हो गया। पिछले वित्त वर्ष में इक्विटी-उन्मुख योजनाओं का फोर्लियो सालाना आधार पर 33.4 प्रतिशत बढ़कर 16.38 करोड़ हो गया।

यूपीआई लेनदेन में आया रिकॉर्ड उछाल

यूपीआई ने अन्य सभी भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है और देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भुगतान तरीका बन गया है।

यूपीआई लेनदेन की संख्या (अरब में)	मूल्य (लाख करोड़ रु में)
2022	45
2023	84
2024	131
2025	185.85
मात्र	260.56
स्रोत : वित्त मंत्रालय)	

फीस ग्राहकों से नहीं लेते, बल्कि खुद वहन करते हैं। उदाहरण के लिए 100 रुपये के क्रेडिट कार्ड भुगतान में दुकानदार को 98 रुपये मिलते हैं और दो रुपये एमडीआर के रूप में कट जाते हैं। लेकिन यूपीआई में कोई एमडीआर नहीं है, यानी दुकानदार को पूरे 100 रुपये मिलते हैं। मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंकिंग

सेवा प्रदाताओं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वित्तीय सेवा विभाग और उपभोक्ता समूहों से बात करेगा।

यह योजना अभी शुरुआती चरण में है और जून में होने वाली बैठक के बाद इसे लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है। इस प्रस्तावित योजना पर उपभोक्ता अधिकार संगठन कंज्यूमर वॉयस के सीईओ अशिम सान्याल ने

ग्राहकों को ऐसे फायदा

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह अंतर स्पष्ट दिखाता है, जहां भुगतान का तरीका चाहे जो हो, फीस एक जैसी रहती है। रिटेल दुकानों पर कुछ दुकानदार ग्राहकों से एमडीआर को वसूलते हैं, जबकि ज्यादातर खुद वहन करते हैं। अगर यूपीआई से खरीदारी पर छूट देने की प्रस्तावित योजना लागू होती है, तो यूपीआई से सामान खरीदने पर भुगतान करने वाले ग्राहक को 100 रुपये की खरीदारी पर सिर्फ 98 रुपये देने होंगे। यानी ग्राहक को 2% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि पेमेंट गेटवे कंपनियां अपनी फीस छोड़ सकती हैं। वहीं, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले को पूरे 100 रुपये देने होंगे।

कहा कि यह कदम ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यूपीआई से भुगतान करने वालों को इनाम मिलेगा।

42% से अधिक वृद्धि: यह योजना ऐसे समय में आ रही है, जब यूपीआई ने अन्य सभी भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है और देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भुगतान तरीका बन गया है।

घरों में सस्ता तेज रफ्तार वाई-फाई उपलब्ध होगा

ये फायदे होंगे

■ **तेज गति:** छह गीगाहर्ट्ज बैंड में वाई-फाई तेज गति से चलेगा। मतलब, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, और ऑनलाइन मीटिंग बिना किसी रुकावट के होंगी।

■ **सस्ता इंटरनेट:** लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, तो कंपनियां कम खर्च में वाई-फाई डिवाइस बना सकेंगी। इससे इंटरनेट सस्ता हो सकता है।

■ **ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगे:** घर में स्मार्ट टीवी, फोन, लैपटॉप जैसे कई डिवाइस आसानी से कनेक्ट हो सकेंगे।

होगा। ड्योन या बिना पायलट वाले हवाई उपकरणों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही वाई-फाई डिवाइस की ताकत (पावर) को 30 डीबीएम तक सीमित रखा गया है, ताकि दूसरे डिवाइस में रुकावट न आए। आसान भाषा में, डिवाइस की सिग्नल ताकत ज्यादा तेज नहीं होगी, जिससे हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) न हो।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

भारत- अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार समझौते को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। बोते दिनों उन्होंने कहा कि भारत अधिकांश टैरिफ हटाने पर सहमत है।

सूत्रों का कहना है कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसके पेशावर व उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं। जहां पर उनकी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। भारत टैरिफ कटौती, कृषि, आईटी सेवाओं और बौद्धिक

भारत ने मालदीव के साथ 13 करार किए

माले, एजेंसी। भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान से नौका सेवाओं को बढ़ाने, समुद्री संपर्क का विस्तार करने और सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इन समझौता ज्ञापनों पर रविवार को हस्ताक्षर किए गए, जो भारतीय अनुदान सहायता योजना- उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना वरण-3 के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए हैं। इस चरण के तहत शुरू की गई 13 परियोजनाओं की कुल अनुदान राशि 10 करोड़ मालदीव रुपये (लगभग 55 करोड़ भारतीय रुपये) है। मालदीव सरकार की ओर से विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। जबकि भारत अपने उत्पादों पर शुल्क संरचना की रक्षा करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि उसके उत्पादों की अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है। इसलिए वह भारत में आने वाले उत्पादों पर शुल्क कटौती या फिर शून्य करने की मांग कर रहा है।

<div><div><div></div><div>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद</div></div></div> <div>कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001</div>	
 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय एवं इसके अनुसंधान संस्थानों में प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर, विधि संवर्ग में विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र और विस्तृत नियम और शर्तें वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं: https://icar.org.in/sites/default/files/Circulars/Vacancy%20Circular_30042025%20%281%29.pdf	
सीबीसी 01303/12/0001/2526	

<div><div><div></div><div>हिन्दुस्तान</div></div></div>
हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड <div> CIN: L21090BR1918PLC000013 </div> पंजीकृत कार्यालय: बुद्ध मार्ग, पटना-800001, भारत <p>फोन: +91 612 2223434</p> कारपोरेट कार्यालय: 5वीं मंजिल, लोटस टॉवर, ए-ब्लॉक, कन्सुमिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110025, भारत फोन: +91 11 66561234, वेबसाइट: www.hmnv.in, ई-मेल: hmnvinvestor@livehindustan.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षेप

विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
	31 मार्च, 2025* लेखापरीक्षित	31 दिसंबर, 2024 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024* लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2025 लेखापरीक्षित
परिचालन से राजस्व	20,125	19,747	18,805	73,289
अवधि के लिए लाभ/(हानि) (असाधारण मदों और कर से पहले)	4,550	1,971	(197)	8,057
कर से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	4,550	1,971	(197)	8,057
कर के बाद की अवधि के लिए लाभ	4,540	1,799	1,074	7,778
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) [जिसमें समाविष्ट कर के बाद की अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक हानि (कर के बाद)]	2,708	1,281	759	5,524
चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य - भा. रु. 10/- प्रति शेयर)	7,367	7,367	7,367	7,367
तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर अन्य इक्विटी				146,064
आमदनी प्रति शेयर (भा. रु. 10/- प्रत्येक का)				
बेसिक और डाइव्यूटेड	6.16	2.44	1.46	10.56
*संदर्भ नोट 5				1.35

टिप्पणियाँ:

1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमनावली, 2015, यथासंशोधित के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूढ़ का एक संक्षेप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट "www.hmnv.in" पर उपलब्ध है।

2. दि. 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और अनुशंसित किया गया तथा 19 मई, 2025 को सम्यन-अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कम्पनी के सॉल्विडक लेखा परीक्षकों ने समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम नई (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमनावली, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार इन परिणामों की लेखा परीक्षण किया तथा एक असंशोधित समीक्षा निष्कर्ष जारी किया।

3. लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("ind AS") साथ में पठित समय-समय पर यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमवली, 2015 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:—

विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
	31 मार्च, 2025 लेखापरीक्षित	31 दिसंबर, 2024 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2025 लेखापरीक्षित
परिचालन से राजस्व	20,125	19,747	18,805	70,409
कर से पहले लाभ/(हानि)	4,527	1,947	(161)	7,974
कर के बाद लाभ	4,517	1,775	1,110	7,695
कुल व्यापक आमदनी	2,685	1,257	795	5,441

5. 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और क्रमशः 31 दिसंबर, 2024 और 31 दिसंबर, 2023 तक (जो वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही का अंत है) प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।



नई दिल्ली
19 मई, 2025

शोभा भर्तार्या
अध्यक्ष

जंबो:
मंबो, तुम्हें पता है बीटा (Beta) क्या होता है?

मंबो:
बीटा नहीं, बेटा होता है... जो मैं अपने मम्मी-पापा का हूँ।

जंबो:
अरे नहीं! बीटा यह बताता है कि म्यूचुअल फण्ड स्कीम का रिटर्न बेंचमार्क के मुकाबले कितना ऊपर-नीचे हुआ है। अगर बीटा 1 है, तो फंड बाजार के साथ-साथ ही चलता है — जितना बाजार बढ़े, उतना ही फंड भी बढ़ेगा अगर बाजार 10% बढ़ता है, तो फंड भी लगभग 10% बढ़ेगा — यानी बाजार के कदम से कदम मिलाकर चलता है।

Baroda BNP PARIBAS MUTUAL FUND


An investor education and awareness initiative by Baroda BNP Paribas Mutual Fund.


KNOW MORE

ऊपर दिए गए परिणाम प्रत्यापित दृष्ट पर आधारित हैं तथा केवल उदाहरण के लिए हैं। एक बार की जाने वाली जो योए कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया के लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही/प्रक्रिया, पते में बदलाव, बैंक अडिरेड, सेबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने आदि की जानकारी के लिए कृपया <https://www.barodabnpnaribasmf.in/investor-centre/information-on-kyc> पर विनित करें कृपया केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंड्स से ही व्यापार करें, जिनके विवरणों का सत्यापन सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर "Intermediaries/ Market Infrastructure Institutions" किया जा सकता है. टैक्स संबंधी निहितार्थों का सत्यापन प्रकृति के लिए, निवेशकों से अनुपेक्ष है कि ये निवेश करने से पहले अपने कर सलाहकार से परामर्श करें। बढ़ती बीजीयता परियाह म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी शिकायतें service@barodabnpnaribasmf.in को प्रेषित की जा सकती हैं और/या इसके लिए आप www.scores.gov.in (सेबी स्कोर्स पोर्टल) पर भी विनित कर सकते हैं. निवेशक <https://smartodr.in/login> पर उपलब्ध ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ओडीआर) के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं, सभी योजना से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

बाजार	30 ^S
शेयर बाजार	
सेंसेक्स	निफ्टी
82059-271.17	24945-74.35
टॉप गेनर	टॉप गेनर
कंपनी	कंपनी
बंद भाव	बंद भाव
बदलाव%	बदलाव%
पावरग्रिड	बजाज ऑटो
बजाज फाइ	श्रीरामफाइ
टॉप लूजर	टॉप लूजर
एटर्नल	एटर्नल
इंफोसिस	ग्रासिम
238.30	238.30
-3.15	-3.15
1559.15	2723.00
-1.92	-2.90

<div>ओएनजीसी</div> <div>ongc</div>	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	कृप्य एवं अनुबंध प्रकोष्ठ
	ओएनजीसी अपतटीय लॉजिस्टिक्स समूह
अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)	
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के ओएनजीसी अपतटीय लॉजिस्टिक्स समूह द्वारा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे और कार निकोबार / ग्रेट निकोबार द्वीपों के बीच यानी चार्टर संचालन के लिए छोटे फिक्स्ड-विंग विमान सेवाओं की सेवाएं हायर करने हेतु पात्र एवं इच्छुक फर्मों/विक्रेताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है।	
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि: 06.06.2025 को या उससे पहले 1700 बजे तक।	
विवरण सहित ईओआई दस्तावेज वेबसाइट https://tenders.ongc.co.in तथा GePNIC-CPPP पोर्टल (https://etenders.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।	

<div>CERC</div> <div>केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग</div>	6वीं, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नोरोजी नगर, नई दिल्ली-110029	<div>राज्यपाल जयरा</div>
	वेबसाइट: www.cercind.gov.in	
यांचिका सं:247 / टीएल / 2025	दिनांक: 15.5.2025	
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस		
बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड, ऊर्जा निधि, पहली मंजिल, 1, बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली –110001 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली, अर्थात् "कर्नाटक में बीजापुर आरईजेड के एकीकरण के लिए पारेषण योजना" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) कार्यान्वित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:		
क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1	बीजापुर (विजयपुर), कर्नाटक के निकट 400 / 220 केवी 5x500 एमवीए पूर्तिग स्टेशन की स्थापना <ul style="list-style-type: none">400 / 220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी-5 नंबर 400 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर (बीजापुर पीएस पर बीजापुर पीएस – रायचूर न्यू लाइन की समाप्ति के लिए) 220 केवी लाइन बे – 10 नंबर 220 केवी सेवशनलाइजर: 1 सेट 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे– 2 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 2 नंबर	प्रभावी तारीख (अर्थात् एस्पबी का अंतरण) से 24 मास (16.01.20277)
भावी स्थान प्रावधान: <ul style="list-style-type: none">400 / 220केवी, 500 एमवीए , आईसीटी – 5 नंबर 400 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर 400 केवी लाइन बे – 6 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान के साथ) 220 केवी लाइन बे – 14 नंबर 220 केवी सेवशनलाइजर: 2 सेट 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे – 2 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 2 नंबर		
2	बीजीपुर पीएस – रायचूर न्यू, 400 केवी (क्वाड एसीएसआर मूज) डी/सी लाइन <ul style="list-style-type: none">400 केवी लाइन बे – 2 नंबर (रायचूर न्यू पर)	
3	बीजापुर पीएस पर 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिपक्टर <ul style="list-style-type: none">420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपक्टर – 2 नंबर 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिपक्टर बे – 2 नंबर	

- सेंटरल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 28.1.2025 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संसुतु किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 247 / टीएल / 2024 में दिनांक 14.5.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- बीजापुर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के **www.grinfra** पर अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.grinfra** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेद